तिब्बती महा-जनक्रान्ति आन्दोलन

इतिहास के विकास क्रम में तिब्बत और चीन दोनों देशों का पृथग् अस्तित्व रहा है। दोनों ने अपनी-अपनी मातृभूमि को अपने बलबूते पर स्वयं की जीविकोपार्जन का स्थान बनाया है। ''चीनी चीन में खुश रहें, तिब्बती तिब्बत में खुश रहें,'' ऐसा पूर्वजों द्वारा स्थापित शिलास्तम्भ पर लिखा हुआ स्पष्टतया प्राप्त है। यह सुभाषित वचन न केवल तिब्बत और चीन के पृथग् राष्ट्र होने का प्रमाण एवं ऐतिहासिक साक्ष है, अपितु पीढ़ियों से कदापि मिटायी न जा सकने वाली तिब्बतियों एवं चीनियों द्वारा शिलालेख पर खुदी हुई सन्धि वर्तमान में भी देखने को मिलती है। इस प्रकार के इतिहास के विकासक्रम में चली आ रही स्वतन्त्रता एवं संप्रभुता को कायम रखना तिब्बतवासियों के अनुपम इतिहास का मौलिक अधिकार और वास्तव में न्याय-संगत है।

फिर भी, बीसवीं शताब्दी के मध्य में चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत में जबरन हिंसात्मक घुसपैठ की। तबसे लेकर अभी तक लगभग पचास वर्षों से अधिक समय बीत चुका है। तिब्बतियों ने गत पचास से अधिक वर्षों में चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा तिब्बत की सभी पहाड़ों एवं नदियों को अपने अधिकार में किये जाने तथा अपनी संस्कृति एवं धर्म को सर्वोत्तम मानने वाले तिब्बतियों पर जबरन चीनी कम्युनिस्ट सरकार के विचार एवं नीतियों को थोपा जाना आदि बहुत अधिक कष्ट सहा है, जो इतिहास के विकासक्रम में बहुत ही कम देखने को मिलता है। लोकतन्त्र एवं स्वतन्त्रता के पक्षधर सम्पूर्ण विश्व में आज के दिन भी वे तिब्बती पूर्ववत् असह्य कठिनाईयाँ एवं यातनाएं भोग रहे हैं। अनेकों शताब्दियों से निरन्तर नेतृत्व करने वाले अपने प्रमुख धर्मगुरु एवं राजा के लिए तिब्बतियों द्वारा ''परम पावन दलाई लामा हजारों वर्षों तक दीर्घायु हों, उन्हें तिब्बत में बुलाया जाय'' इतना मात्र कहे जाने से किसी तिब्बती को आठ वर्ष की कठोर सजा दी जाती है, जो दास-प्रथा एवं सामन्तवाद में भी देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार की यातनाओं से पूर्ण जीनव की स्थिति में भी स्वतन्त्रता रूपी सूरज के उदय होने की तिब्बती जनता प्यासे व्यक्ति द्वारा पानी की आशा की भाँति आशाभरी निगाहों से इन्तजार कर रही है।

सन् 2002 से आज तक तिब्बत की समस्या पर प्रवासी तिब्बती सरकार एवं चीन सरकार के बीच छह बार सीधी बातचीत हो चुकी है। इस क्रम में तिब्बती प्रवासी सरकार ने अपनी ओर से काफी उदार नीति अपनाई और रियायतें बरती हैं, किन्तु उन वार्ताओं साक्षात् लागू करने के सम्बन्ध में चीन सरकार ने प्रगति की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ तक कि उनकी ओर से एक अच्छा संकेत तक भी नहीं किया गया, बल्कि उसके विपरीत वे निरन्तर परम पावन जी की निन्दा ही करते रहे। इसे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वह तिब्बती की संस्कृति की रक्षा एवं विकास के नाम पर झूठा दिखावा करते हुए तिब्बती धर्म एवं संस्कृति आदि, पूर्वजों की अत्यन्त गौरवशाली विरासत का विनाश कर रहे हैं, तथा उसके स्वरूप को भी बदल रहा है। इसके अतिरिक्त तिब्बत की बहुमूल्य भौतिक वस्तुओं, खनिज पदार्थों, भूमिगत निधियों आदि अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाओं को चीन में हस्तान्तरित कर रहा है।

संक्षेप में, चीन का मानना है कि चीनी कम्युनिस्ट सरकार के हित में किये जाने वाले समस्त कार्य न्यायसंगत हैं और तिब्बती द्वारा तिब्बतियों के हित में किये जाने वाले समस्त कार्य न्यायसंगत नहीं हैं। अर्थात् यदि कोई चीनी किसी तिब्बती की हत्या करता है, तो वह न्याय संगत है और यदि कोई तिब्बती अपने अमूल्य धर्म एवं संस्कृति के सम्बन्ध में आवाज ऊँची करता है, तो वह न्याय संगत नहीं माना जाता है, अपितु उस पर दोषारोपण कर दण्डित किया जाता है। तिब्बत की इस प्रकार की असहनीय स्थिति को देखकर तो देव एवं भूत-प्रेत भी आँसू बहाते होंगे और नरक एवं प्रेत योनि के प्राणी भी दुःखी होते होंगे।

इस कारण आज हम पाँच प्रवासी गैर-सरकारी तिब्बती संगठन के सदस्यगण नव-नियुक्त चीनी अधिकारियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि चीन एवं तिब्बत दोनों देशों के भावी दूरगामी हित के लिए अभी से एक अच्छा एवं प्रभावी कदम उठाया जाय और इसके लिए हम निम्नलिखित अन्तिम सुझावों की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं-

1. परम पावन दलाई लामा को यथाशीघ्र तिब्बत बुलाया जाय,
2. कम्युनिस्ट चीनी तिब्बत से वापस लौट जाय,
3. समस्त राजनैतिक कैदियों को रिहा किया जाय,
4. तिब्बत की स्वतन्त्रता का समाधान किये बिना चीन में ओलम्पिक के आयोजन को अनुचित ठहराया जाय।

1. समस्त तिब्बती समुदाय द्वारा कई शताब्दियों से पूज्य एवं सम्मानित परम पावन दलाई लामा जी महान् तिब्बत राष्ट्र के एकमात्र धर्मगुरु एवं राष्ट्राध्यक्ष हैं। अभी भी परम पावन जी के यथाशीघ्र स्वदेश पधारने हेतु तिब्बती जनता आशावान है। किन्तु दूसरी ओर चीनी सरकार लगातार परम पावन जी की निन्दा करती आ रही है। यहाँ तक कि इतिहास के विकासक्रम में मौजूद लामा एवं टुल्कु के अवतार को प्रमाणित करने की तिब्बत की अनूठी ऐतिहासिक परम्परा, पारम्परिक रीति-रिवाज एवं श्रदालु जनता की आशाओं को नजरअंदाज कर नेस्तनाबूद करने अमादा है अर्थात् टुल्कु के अवतार को प्रमाणित करने के तिब्बती आध्यात्मिक एवं परम्परागत अधिकार को भी मोड़ने का भरसक प्रयास कर रही है और तिब्बत की सम्पूर्ण मानवीय एवं भौगोलिक सम्पदाओं पर भी प्रभुत्व जमा रही है।

2. चीन द्वारा तिब्बत में चीनी जनसंख्या के स्थानान्तरण की सीमा इतिहास के क्रम में सर्वाधिक चरम पर है और कम जनसंख्या वाली तिब्बती जनता अपने ही देश में अल्पसंख्यक बना दिये गये हैं, जो दूर चीन से आये अपार जनसंख्या वाले चीनियों के बीच विलुप्त होते जा रहे हैं। इस कारण तिब्बती जाति को परिलक्षित करने वाली धर्म एवं संस्कृति, रीति-रिवाज सहित आधारभूत भाषा भी बिलकुल ही विलुप्त होने की कगार पर पहुँच चुकी है। तिब्बतियों को मौलिक-अधिकार, धार्मिक-अधिकार एवं भाषण का अधिकार आदि से वंचित किया जा रहा है। इतना कुछ खोने के बावजूद भी सुदूर चीन से आयी चीनी जनता के अधिकार में कैद तिब्बती समुदाय परतन्त्र की जंजीरों से यथाशीघ्र मुक्त होने की आस लगाये बैठी है।

3. परम पावन दलाई लामा द्वारा घोषित पनछेन रिनपोछे तेनजिन गेदुन छोस् क्यि ञिमा सहित ज-ड्रल रिनपोछे, लोसङ् तेनजिन, टुल्कु तेनजिन देलेग रिनपोछे, बङ्रि रिनपोछे, डोनमा क्यब, रुङ्-ग्यस् अ-डग, अ-ठुग लोपो आदि तिब्बती राजनैतिक कैदी, जो चीन के विभिन्न कारागारों में कैद हैं, उन्हें न केवल बिना किसी पूर्व शर्त के रिहा किया जाना चाहिए, अपितु उन्हें तथा इसके पूर्व रिहा किये जा चुके राजनैतिक कैदियों के साथ और इसके अतिरिक्त उनके परिवार जनों के साथ भी सामान्य जनता के अनुरूप व्यवहार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, तिब्बती जनता का दायित्व वहन करने वालों के सत्य की आवाज का भी स्पष्ट एवं उचित जवाब दिया जाना चाहिए।

4. विश्व ओलम्पिक खेलों की मेजबानी प्राप्त करने वाले देश को मानवाधिकार, शान्ति, धार्मिक अधिकार, भाषण का अधिकार एवं इतिहास आदि के प्रति निश्चित रूप से सम्मान एवं मान्यता आदि इन सभी पूर्व शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, जबकि अभी चीन इन सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है। अत: चीन सरकार को चाहिए कि वह इन सभी शर्तों को निश्चित रूप से लागू करें। इन समस्त पूर्व शर्तों को पूरा किये बिना ही यदि चीन ताकत के बल पर लगातार इन शर्तों की अनदेखी करता है, तो उसे भी ओलम्पिक के आयोजन की मेजबानी का कोई अधिकार नहीं है।

विश्व ओलम्पिक आयोजक समिति का भी यह दायित्व बनता है कि वह अधिकारपूर्वक न केवल चीन सरकार पर इस संदर्भ में दबाव डालें, अपितु ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले राष्ट्रों को भी स्वभाविक रूप से इसमें भाग लेने से रोकें।

पूर्व में जब रशिया ने सन् 1980 में अफगानिस्तान में जबरन घुसपैठ कर सैनिक कार्यवाही की, तब अमेरिका आदि पचास से भी अधिक देशों ने उसी वर्ष मास्को में होने वाले ओलम्पिक खेलों का बहिष्कार किया था। वर्तमान में चीनी सरकार द्वारा तिब्बत पर जबरन कब्जा किये जाने का मामला भी पूर्व में अफगानिस्तान की स्थिति के समान ही है, बल्कि तिब्बत की स्थिति उससे भी अधिक दर्दनाक एवं घृणात्मक है। अत: वर्ष 2008 के ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले देशों को इतिहास का सम्मान करते हुए, समयानुकूल दायित्व का निर्वाह करते हुए तथा लोकतन्त्र एवं स्वतन्त्रता को सम्मान देते हुए इन सभी अच्छी परम्पराओं का पूर्व से भी अधिक विकास के लिए आपसी सहयोग देना चाहिए।

8 अगस्त, 2008 ई. के पहले यदि चीन सरकार उपरोक्त आवश्यकताओं एवं पूर्व शर्तों का निर्वाह नहीं करता है, तो हम वर्ष 2008 के 10 मार्च से व्यापक रूप से अनिश्चितकालीन ''तिब्बती महा-जनक्रान्ति आन्दोलन'' का नेतृत्व कर अपने कर्त्तव्यों के अधिकार को स्वयं निर्धारित करेंगे, जो तिब्बतियों के लिए इतिहास द्वारा प्रदत्त दायित्व है, समयानुकूल कर्त्तव्य है, जनता की आशा है और मृत एवं जीवित वीर-वीराङ्गना राष्ट्रभक्तों की एकमात्र अन्तिम इच्छा है।

अत्यन्त कष्टप्रद इस गौरवशाली महान आन्दोलन को हमें अवश्य ही सफल बनाना चाहिए, इस कार्य में कदापि देरी एवं लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। राष्ट्र के समस्त भाई-बहिनों को एकजुट होकर एकसूत्र में बँध जाना चाहिए और पूरी शक्ति के साथ दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। सभी प्रकार की सामग्रियों को उपलब्ध कराते हुए पीड़ित तिब्बती जनता के संरक्षणार्थ एक दृढ़ लोहे का दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए।

हमारे संघर्ष की जीत के लिए जनता ही शक्ति का प्रतीक एवं मूल स्रोत है, इसलिए ''तिब्बती महा-जनक्रान्ति आन्दोलन'' में भाग लेने वालों का साहस एवरेस्ट के समान अडिग एवं अचल है। इससे दूर रहकर आराम से सोने वाला व्यक्ति हवा से बहाये जाने वाले कागज के टुकड़े से भी हल्का है।

आज हम करो अथवा मरो की अन्तिम स्थिति में पहुँच चुके हैं। चीन के साथ चल रही शान्ति वार्ता में आशा करना खुले आसमान में तलवार भाँजने की भाँति निरर्थक है। इसलिए सभी तिब्बती भाई-बहिनों को स्वयं दिमागी तौर पर तैयार होना, अपने आप पर पूरा विश्वास एवं आशा होना, आत्म-सम्मान एवं आत्म-विश्वास होना बहुत जरूरी है और उन्हें घमण्ड एवं अभिमान रहित होकर तिब्बती जाति की अच्छी परम्परा के निरन्तर विकास के लिए कार्य करना भी आवश्यक है। इसके साथ ही, स्वयं को महान तिब्बत राष्ट्र की स्वतन्त्रता एवं उसकी सुख-शान्ति के लिए अर्पित करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, जो हिमवत् तिब्बत प्रदेश के वंशानुगत सुपुत्रों का उत्तम भावी विचार है और उनके जीवन का वास्तविक लक्ष्य है।

यह ''तिब्बती महा-जनक्रान्ति आन्दोलन'' हमारी स्वतन्त्रता संघर्ष की तरफ जनता का मुख मोड़ने का एक महान आन्दोलन होगा, तिब्बत के इतिहास में एक सार्थक आन्दोलन होगा। फिर भी, बहुत अधिक घमण्डी तथा अभिमानी शत्रु को समझाने में सक्षम होना अथवा न होना तो हम सभी की नियत एवं कार्यान्वयन पर निर्भर है।